



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1940 (श10)

(सं0 पटना 705) पटना, बुधवार, 25 जुलाई 2018

सं० अ0सं0क0 -08-15/2010 खंड-1-1006

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

23 जुलाई 2018

**विषय :-** अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका के कंडिका-4 एवं 7 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में ।

1. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाक शुदा महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि रू0 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र से बढ़ाकर रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मंत्रिपरिषद के मद संख्या- 29 दिनांक 11.12.2017 द्वारा दी गई है । उक्त मार्गनिर्देशिका के कंडिका- 4 एवं 7 में निम्न संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

**कंडिका- 4** यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों में इस योजना के आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं अनुलग्नकों की जाँच विहित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित की जायेगी। योग्य लाभुकों के चयन एवं योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर निम्न प्रकार से जिला चयन समिति गठित की जाती है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. उप विकास आयुक्त   | - अध्यक्ष    |
| 2. जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी | - सदस्य      |
| 3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी:   | - सदस्य-सचिव |

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी चयनित लाभुकों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायेंगे । निदेशालय सूची के अनुसार अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित करेगा ।

**कंडिका- 7** “अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा इस योजना में उपलब्ध कराई गई राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय प्रचार-प्रसार, संविदा सेवा, विज्ञापन प्रकाशन आदि प्रशासनिक मद में किया जायेगा”।

3. उक्त प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. उक्त संशोधन के पश्चात् योजना के मार्गनिर्देशिका निम्न प्रकार होगी:-

(1) **अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना**।- “राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 10,000/- (दस हजार) रुपया दिया जाता रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000/- (पचीस हजार) रुपया किया जायेगा।

(2)(i) **मुस्लिम परित्यक्ता महिला**।- ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी हो परन्तु उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से परित्याग कर दिया गया हो तथा उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो, अथवा पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो, ऐसी महिला को योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला समझा जाएगा।

(ii) **मुस्लिम तलाकशुदा महिला**।- ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो तथा उनके जीवनयापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो ऐसी महिला इस योजनान्तर्गत तलाकशुदा समझी जाएगी।

(3) **आवेदन हेतु अनिवार्य दास्तावेज**।-आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करने होंगे।

(क) **घोषणा पत्र**।- आवेदिका द्वारा स्थानीय दो गवाहों, जो करीबी रिश्ते में ना हों, के समक्ष किया गया इस आशय का घोषणा-पत्र। जिसमें गवाहों का नाम, पता एवं मोबाईल नं० स्पष्ट रूप से अंकित हो।

(ख) **अनुशंसा पत्र/प्रमाण पत्र**।- परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदिका द्वारा निम्न में से किसी एक के द्वारा निर्गत किया गया परित्यक्ता/तलाकशुदा होने के आशय का अनुशंसा पत्र अथवा प्रमाण पत्र।

i. **जनप्रतिनिधि**।- मुखिया/सरपंच/नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत से संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि/प्रखंड प्रमुख/पंचायत समिति के सदस्य/विधान मंडल के सदस्य अथवा सांसद।

ii. **न्यायालय सरकारी संस्था/कार्यालय/पदाधिकारी**।- परिवार न्यायालय /प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ अनुदानित मदरसा के हेड मोदरिस/सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाध्यापक/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी।

iii. **राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित मुस्लिम समुदाय की मानक/निबंधित संस्थान/जिला औकाफ कमिटी के सचिव/निबंधित वक्फ के मोतवल्ली।**

(ग) **आयु प्रमाण पत्र** :- आवेदन देने वाली महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष की होगी। आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो/मतदाता प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट/कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र।

(घ) **आय प्रमाण पत्र** : मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएँ जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4,00,000/- (चार लाख) रुपये से कम हो। अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।

(च) **पति के मानसिक विकलांगता के मामलों में** जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(छ) **आवेदन पत्र के साथ** अद्यतन पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो स्वयं अभिप्रमाणित हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

(4) **योजना का क्रियान्वयन**।- यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों में इस योजना के आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं अनुलग्नकों की जाँच विहित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित की

जायेगी। योग्य लाभुकों के चयन एवं योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर निम्न प्रकार से जिला चयन समिति गठित की जाती है :-

1. उप विकास आयुक्त — अध्यक्ष
  2. जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी — सदस्य
  3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी: — सदस्य-सचिव
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी चयनित लाभुकों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायेंगे। निदेशालय सूची के अनुसार अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित करेगा।

(5) **अल्पसंख्यक गरीब मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा की सत्यता की जाँच।**— मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा से संबंधित जाँच एक महीने में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से करायी जाएगी। कुल आवेदनों में से कम से कम 10% आवेदनों की जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

(6) **अन्य पात्रता का मापदण्ड :-**

- (i) बेवा/मुस्मात महिला इस योजना के पात्र नहीं होगी।
  - (ii) इस योजना का लाभ जीवन काल में केवल एक बार ही मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी द्वारा आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य होगा।
- (7) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा इस योजना में उपलब्ध कराई गई राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय प्रचार-प्रसार, संविदा सेवा, विज्ञापन प्रकाशन आदि प्रशासनिक मद में किया जायेगा।
- (8) मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएँ विहित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी।
- (9) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की प्रविष्टि एक पंजी में कर लेंगे जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से होगा :-

क्र.	आवेदिका का नाम	उम्र	पिता/माता का नाम	आवेदिका का पता	परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा	अनुशंसा / प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी/ संस्था का नाम	स्वघोषणा पत्र/ दिनांक	आधार सं०	मोबाईल न०	बैंक का नाम	खाता संख्या (स्वयं का)	बैंक ब्रांच का IFSC कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (10) आवेदन पत्रों के साथ स्वयं का बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की छायाप्रति (आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड) ( के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (11) लाभुकों को एन0आई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैंक खाता में राशि आंतरित की जाएगी।
- (12) इस योजना का लाभ संकल्प की निर्गत तिथि से पूर्व से लंबित आवेदनकर्ताओं जिनको अनुदान-राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है, को भी प्राप्त होगा।
- (13) लाभुकों का नाम एवं पता विभागीय वेबसाईट एवं उर्दू/हिन्दी के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।”

आदेश:-

आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के विशेष सचिव-सह- निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 705-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>